

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2023—पौष 30, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 दिसम्बर 2022

क्रमांक ई1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (2005), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन को केवल मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

2. श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), मिशन संचालक, समग्र शिक्षा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसायटी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

4. श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड के पद पर पदस्थ करता है।

श्री पदुम सिंह एल्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत के प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

5. श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

6. श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

7. सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, महिला एवं बाल विकास को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

8. श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर तथा संयुक्त सचिव, कृषि विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

9. श्री अजीत वसंत, भा.प्र.से. (2013), आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है।

10. श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. (2014), कलेक्टर, जिला-नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-धमतरी के पद पर पदस्थ करता है।

11. श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

12. श्रीमती तुलिका प्रजापति, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, कृषि विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य दुर्ग महासंघ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

13. श्री भगवान सिंह उइके, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, जिला-कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, अंतागढ़, जिला-कांकेर के पद पर पदस्थ करता है।

14. श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से. (2017), अपर कलेक्टर, जिला-कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

श्री चंद्रकांत वर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत के प्रबंध संचालक, प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

15. सुश्री रेना जमील, भा.प्र.से. (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 1-7/2022/16.—राज्य शासन द्वारा गठित नये जिलों के संदर्भ में संचालनालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के निम्नलिखित मैदानी कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में निम्न राजस्व जिले सम्मिलित होंगे :—

क्रमांक (1)	कार्यालय का नाम (2)	कार्यक्षेत्र (3)
1.	कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिलासपुर.	बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, राजस्व जिले
2.	कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़.	रायगढ़, जशपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, राजस्व जिले
3.	कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, राजनांदगांव.	राजनांदगांव कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, राजस्व जिले.
4.	कार्यालय सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जांजगीर-चांपा.	जांजगीर-चांपा, सक्ती, राजस्व जिले
5.	कार्यालय सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, अम्बिकापुर.	सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, राजस्व जिले.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 1-7/2022/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2022/16, दिनांक 07-12-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 7th December 2022

No. F 1-7/2022/16.—With reference to the new districts formed by the State Government, the following revenue districts will be included in the jurisdiction of the following field offices of the Directorate of Industrial Health and Safety :—

S.No. (1)	Name of the office (2)	Jurisdiction (3)
1.	Office of the Deputy Director Industrial Health and Safety, Bilaspur.	Bilaspur, Mungeli, Gaurela-pendra-Marwahi, revenue districts.

(1)	(2)	(3)
2.	Office of the Deputy Director Industrial Health and Safety, Raigarh.	Raigarh, Jashpur, Sarangarh-Bilaigarh revenue districts
3.	Office of the Deputy Director Industrial Health and Safety, Rajnandgaon.	Rajnandgaon, Kabirdham, Mohla-Manpur-Ambagarh-Chouki, Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai, revenue districts.
4.	Office of the Assistant Director Industrial Health and Safety, Janjgir-Champa.	Janjgir-Champa, Sakti, revenue districts.
5.	Office of the Assistant Director Industrial Health and Safety, Ambikapur.	Surguja, Surajpur, Balrampur, Koriya, Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur, revenue districts.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
ASHUTOSH PANDAY, Deputy Secretary.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्रमांक/6806/एफ-03/63/विविध/2022/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा उद्यानिकी महाविद्यालय, जिला गौरेला-पैण्ड्रा-मरवाही का नाम “महंत बिसाहू दास, उद्यानिकी महाविद्यालय, जिला-गौरेला-पैण्ड्रा-मरवाही” किया जाता है।

2. उक्ताशय पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 196/सा.प्र.वि. कक्ष-5, दिनांक 12-12-2022 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 3-62/2008/गृह-दो.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन किया गया है।

2. अतः उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15-11-2020 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में श्रीमती रामकली यादव सदस्य को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये सदस्य नियुक्त किया गया है।

3. उक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम की धारा-41(1) के तहत श्रीमती रामकली यादव सदस्य, को पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में सदस्य पद पर 02 वर्ष की पुनःनियुक्ति (re-appointment) दी जाती है।

4. शेष शर्तें यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ-1-49/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा (भापुसे-2001), पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग, छ.ग. को दिनांक 09 जनवरी 2023 से 18 जनवरी 2023 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 06, 07 एवं 08 जनवरी 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. छाबड़ा, भापुसे आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश काल में डॉ. छाबड़ा (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. छाबड़ा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

5. डॉ. आनंद छाबड़ा (भापुसे-2001), पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे-2005, (प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, जिला रायपुर को छोड़कर रायपुर रेंज के शेष जिले) को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 जनवरी 2023

क्रमांक एफ-7-12/2022/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री बी. एस. ध्रुव (भापुसे-2006), पुलिस उप महानिरीक्षक, छसबल, दक्षिण रेंज, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 05 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 (कुल 15 दिवस) तक का मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. ध्रुव, भापुसे आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, छसबल, दक्षिण रेंज, बस्तर, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश काल में श्री ध्रुव (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ध्रुव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

5. श्री बी. एस. ध्रुव (भापुसे-2006), पुलिस उप महानिरीक्षक, छसबल, दक्षिण रेंज, बस्तर, जगदलपुर के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री दाऊलुरी श्रवण, (भापुसे-2008), पुलिस उप महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्रमांक 4061/2061/2022/16 (पार्ट).—राज्य शासन एतद्वारा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में निम्नानुसार 02 राज्य विधानसभा सदस्यों को मनोनित किया जाता है :—

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | श्रीमती संगीता सिन्हा
क्षेत्र क्रमांक-59, संजारी-बालोद | — | सदस्य |
| 2. | श्री अनूप नाग
क्षेत्र क्रमांक-79, अंतागढ़ | — | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्रमांक 4055/1584/2022/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्र. एफ 10-8/2018/16, दिनांक 28-04-2018 में असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना की कण्डिका (ब) में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

(ब) योजना हेतु पात्रता —

योजना का लाभ लेने हेतु महिला असंगठित कर्मकार का मंडल में पंजीयन बच्चे के जन्म के 90 दिवस पूर्व होना अनिवार्य है.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

No. 4055/1584/2022/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Unorganized Workers Social Security Act, 2008, the State Government hereby issued notification No. F 10-8/2018/16, dated 28-04-2018 Chhattisgarh Unorganized Workers State Social Security Board inserts the following amendments in clause (b) of the Asangathit Karmkar Prsooti Sahayata Yojana —

- (B) **Eligibility for the scheme**— It is mandatory to have registration of female unorganized workers in the Board, 90 days before the birth of the child, to take advantage of the scheme.

The above amendment will be effective from the date of notification.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्रमांक 4057/1584/2022/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्र. एफ 10-2/2015/16, दिनांक 11-03-2015 में सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना की कण्डिका (2) में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित

करती है :—

(2) **योजना हेतु पात्रता —**

2.1 “योजना का लाभ लेने हेतु महिला सफाई कर्मकार का मंडल में पंजीयन बच्चे के जन्म के 90 दिवस पूर्व होना अनिवार्य है.”

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

No. 4057/1584/2022/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Unorganized Workers Social Security Act, 2008, the State Government hereby issued notification No. F 10-2/2015/16, dated 11-03-2015 Chhattisgarh Unorganized Workers State Social Security Board inserts the following amendments in clause (2) of Safai Karmkar Prasooti Sahayata Yojana —

(2) **Eligibility for the scheme—** It is mandatory to have registration of female cleaning workers in the Board, 90 days before the birth of the child, to take advantage of the scheme.

The above amendment will be effective from the date of notification.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्रमांक 4059/1584/2022/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्र. एफ 10-11/2018/16, दिनांक 02-08-2018 में ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना की कण्डिका (ब) में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती है :—

(ब) **योजना हेतु पात्रता —**

“योजना का लाभ लेने हेतु महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक का मंडल में पंजीयन बच्चे के जन्म के 90 दिवस पूर्व होना अनिवार्य है.”

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

No. 4059/1584/2022/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Unorganized Workers Social Security Act, 2008, the State Government hereby issued notification No. F 10-11/2018/16, dated 02-08-2018 Chhattisgarh Unorganized Workers State Social Security Board inserts the following amendments in clause (b) of the Mahila Theka Shramik, Gharelu Mahila Kamgar evam Mahila Hamal Prasooti Sahayata Yojana —

(B) **Eligibility for the scheme—** It is mandatory to have registration of female contract workers, female domestic workers and female hamal workers in the Board, 90 days before the birth of the child, to take advantage of the scheme.

The above amendment will be effective from the date of notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहू, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक/एफ 19-01/2021/25-1.—विभागीय आदेश दिनांक 31-10-2022 द्वारा छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, रायपुर में अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के संचालन मंडल के नियमावली में संशोधित अधिसूचना दिनांक 09-12-2022 के द्वारा उपाध्यक्ष 01 पद प्रतिस्थापित किया गया है।
3. अतः राज्य शासन एतद्वारा पूर्व आदेश दिनांक 31-10-2022 में मनोनित माननीय सदस्य श्री खिलावन बघेल को उपाध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्ति करता है।
4. यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक/एफ 19-02/2021/25-1.—विभागीय आदेश दिनांक 31-10-2022 द्वारा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, रायपुर में अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के संचालन मंडल के नियमावली में संशोधित अधिसूचना दिनांक 09-12-2022 के द्वारा उपाध्यक्ष का 01 पद प्रतिस्थापित किया गया है।
3. अतः राज्य शासन एतद्वारा पूर्व आदेश दिनांक 31-10-2022 में मनोनित माननीय सदस्य श्री विष्णु विश्वकर्मा को उपाध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्ति करता है।
4. यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक/एफ 19-03/2021/25-1.—विभागीय आदेश दिनांक 31-10-2022 द्वारा छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड, रायपुर में अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के संचालन मंडल के नियमावली में संशोधित अधिसूचना दिनांक 09-12-2022 के द्वारा उपाध्यक्ष का 01 पद प्रतिस्थापित किया गया है।
3. अतः राज्य शासन एतद्वारा पूर्व आदेश दिनांक 31-10-2022 में मनोनित माननीय सदस्य श्री दुखवा राम निर्मलकर को उपाध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्ति करता है।
4. यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एमरेंसिया खेस्स, उप सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 1-01/2022/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अतुल कुमार शुक्ला, भा.व.से. (1986) प्रधान मुख्य वन संरक्षक.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	प्रबंध संचालक, छ.ग. अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) रायपुर (राज्य प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपते हुए)
2.	श्री आशीष कुमार भट्ट, भा.व.से. (1988) प्रधान मुख्य वन संरक्षक.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर.
3.	श्री अनिल कुमार राय, भा.व.से. (1990) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.	प्रबंध संचालक, छ.ग. अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) रायपुर.	अतिरिक्त प्रबंधन संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर (राज्य प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4663/अ-82/भू-अर्जन/2022-23.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है.

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	तोतर	02	0.050 हे.	आदनार-तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-तोतर की निजी भूमि हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-12-2022 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन तोतर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	आदनार-तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-तोतर की निजी भूमि हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां 0.050 हेक्टेयर
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	1088.81 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	प्रस्तावित सेतु निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने-जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोण्डागांव, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4666/अ-82/भू-अर्जन/2022-23.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है.

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव-शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16	01	0.098 हे.	कोण्डागांव-शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 में स्थित कोकोनट प्लांट से होते हुए ग्राम-भीरागांव को जोड़ने हेतु निर्मित मार्ग के 0.098 हेक्टेयर भूमि मार्ग में आने वाले भूमि हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21-12-2022 को समय 11.00 बजे स्थान शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 कोण्डागांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कोण्डागांव-शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड-16 में स्थित कोकोनट प्लांट से होते हुए ग्राम-भीरागांव को जोड़ने हेतु निर्मित मार्ग के 0.098 हेक्टेयर भूमि मार्ग में आने वाले भूमि हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां 0.098 हेक्टेयर
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	प्रस्तावित पहुंच मार्ग निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने-जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 16 नवम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/13764/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	हरदीबाजार	बोईदा	2.066 हे.	बोईदा मुख्य मार्ग से नायकपारा तिलैयापारा फुटहामुड़ा मार्ग लंबाई 2.76 कि.मी. निर्माण हेतु अर्जन.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24-12-2022 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन बोईदा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बाईदा मुख्य मार्ग से नायकपारा तिलैयापारा फुटहामुड़ा मार्ग लंबाई 2.76 कि.मी. निर्माण हेतु अर्जन.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	37 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	37 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	16
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	01 सार्वजनिक मंच, देवस्थान
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 506.39 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन हेतु बारहमासी सड़क
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

रा.प्र.क्र. 02/अ-82/14630/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	हरदीबाजार	रामपुर	0.216 हे.	रामपुर मोड़ से डिपरीपारा मुरली मार्ग लंबाई 2.96 कि.मी. निर्माण.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18-01-2023 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन रामपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर मोड़ से डिपरीपारा मुरली मार्ग लंबाई 2.96 कि.मी. निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 482.85 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन हेतु बारहमासी सड़क
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/14634/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	हुकरा	0.843 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11-01-2023 को समय 12.00 बजे से स्थान हुकरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	15 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	15 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्रमांक 10/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	रतनपुर	उमरमरा प.ह.नं.-35	1.737	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा	अरपा-भैसाझार बैराज परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्रमांक 19/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-सरगुजा
 - (ख) तहसील-लुण्ड्रा
 - (ग) नगर/ग्राम-बरडीह
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
846	0.251
848/5	0.049
856/3	0.130

(1)	(2)	(1)	(2)
761	0.112	55/2	0.032
113/1	0.041	140	0.101
129/1	0.064	84/2	0.121
61	0.081	54/2	0.041
141	0.104	106/2	0.103
86	0.061	60/2	0.068
55/1	0.101	2	0.042
107/1	0.008	112	0.088
1/3	0.042	851/2	0.021
4	0.048		
702/4	0.408	योग	59
855/2	0.061		5.324
852	0.162	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरडीह झखरी	
846/6	0.258	व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.	
850/2	0.061	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
762	0.188	(राजस्व), धौरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
115/1	0.070	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
129/2	0.064	कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
134/1	0.096		
142/2	0.064		
83	0.085		
59/1	0.042		
1/2	0.028		
6/3	0.033		
5	0.024		
6/1	0.040		
854/2	0.026		
851/1	0.137		
849	0.128		
850/1	0.061		
702/7	0.170		
111/2	0.032		
127	0.032		
134/2	0.068		
84/3	0.142		
54/1	0.081		
59/2	0.042		
6/2	0.032		
60/3	0.074		
106/1	0.045		
60/1	0.074		
896/6	0.088		
856/4	0.129		
845/4	0.303		
757	0.061		
702/8	0.120		
111/1	0.086		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरडीह झखरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धौरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्रमांक 02/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-पेण्डीडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अनुसूची
(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन—
182	0.186	(क) जिला-बिलासपुर
		(ख) तहसील-बिल्हा
		(ग) नगर/ग्राम-अमेरी अकबरी
		(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.235 हेक्टेयर
योग	0.186	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.	161/5	0.186
	161/4	0.049
	योग	0.235

बिलासपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022	
----------------------------------	--

क्रमांक 03/अ-82/2021-22.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/2800/आर-2095/2017/25-2

नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2022

उर्दू पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर (संशोधन) नियमावली 2022

उर्दू पुस्तकालय एवं वाचनालय नियमावली 2017 में संशोधन करने हेतु नियम

उर्दू पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर में छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा निम्नलिखित में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—

- (1) यह नियम उर्दू पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर (संशोधन) नियमावली 2022 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उर्दू पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर पर होगा.
- (3) यह नियमावली शासन स्वीकृति के तारीख से प्रवृत्त होगा.

नियम 4 में संशोधन :— उर्दू पुस्तकालय एवं वाचनालय नियमावली 2017 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में निर्दिष्ट है) नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

“राज्य के प्रमुख स्थानों पर संस्थाओं के साथ अनुबंध कर उर्दू पुस्तकालय, वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर की सुविधा उपलब्ध कराना.”

नियम 4 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

“प्रदेश के शायरों तथा अदीबों द्वारा स्वरचित उर्दू भाषा की पुस्तकें व उर्दू भाषा के फरोग (विकास) के लिए उर्दू की पुस्तकें, प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें, उर्दू व हिन्दी दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पत्रिकाएं, समाचार-पत्र पत्रिकाएं एवं अन्य उपयोगी पुस्तकों का अधिक से अधिक संग्रहण करना एवं उपलब्ध कराना. उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू पुस्तकालय, वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर स्थापना के पश्चात् केन्द्र संचालन हेतु अनुबंधित संस्थानों को उर्दू-हिन्दी-अंग्रेजी पुस्तक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, कम्प्यूटर सेट, फर्नीचर, सेन्टर संचालन हेतु डी.एम.एफ (DMF) मद से अनुदान हेतु जिलाध्यक्ष को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा. एवं NCPUL द्वारा छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी को एक वर्षीय उर्दू एवं अरबी डिप्लोमा कोर्स संचालन किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी अनुबंधित कम्प्यूटर सेन्टर में भी कोर्स का संचालन करना तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित चॉईस सेन्टर का उर्दू पुस्तकालय वाचनालय केन्द्र में पंजीयन कराकर संचालन करना.”

नियम 4 के उपनियम (5) में निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाये अर्थात् :—

“उर्दू अकादमी द्वारा सेन्टर में सलाहकार संचालन समिति का गठन एवं पत्र-पत्रिकाओं का (नियम एवं शर्तों) का निर्धारण एवं छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी से अनुबंधित सेन्टर के संचालन में सुचारू रूप से संचालित नहीं होने पर छ.ग. उर्दू अकादमी द्वारा अनुबंध निरस्त करने का विशेषाधिकार होगा. निरस्त करने पर छ.ग. उर्दू अकादमी द्वारा प्रदाय की गई समस्त सामग्री संस्था स्वयं के व्यय से कार्यालय में जमा करना होगा.”

3. **नियम 5 में संशोधन :—** मूल नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर का पंजीयन — राज्य के विभिन्न स्थानों पर उर्दू अकादमी द्वारा अनुबंध कर संचालित किये जाने वाले पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर का अकादमी में पंजीयन कराना आवश्यक होगा. इसके लिये अकादमी द्वारा निर्धारित फार्म में निर्धारित शुल्क 100/- रु. जमा कर आवेदन करना होगा, आवेदन को स्वीकार करने का अधिकार अकादमी का होगा. आवेदन फार्म अस्वीकार होने की स्थिति में किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर करने का अधिकार आवेदक को नहीं होगा.

4. **नियम 6 में संशोधन :—** मूल नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

“छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अनुबंध से संचालित होने वाली पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर में विभिन्न विषयों से संबंधित उर्दू भाषा की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, कम्प्यूटर सेन्टर संबंधित किताबें, एवं अन्य उपयोगी पुस्तकें मनोरंजन, शिक्षा तथा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास में प्रकाशित होने वाली पत्रिकायें (सप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक) तथा उर्दू-हिन्दी-अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले दैनिक व समाचार पत्र पाठकों को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा. उर्दू भाषा सीखने हेतु अकादमी व अन्य माध्यमों से प्राप्त पाठ्य सामग्री व उर्दू साहित्य भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा.” सेन्टर सुचारू रूप से संचालित होने पर पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करायी जायेगी.

5. **नियम 20 स्थापित :—** नियम 20 उपनियम (1) से (5) तक में निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाये अर्थात् :—

कम्प्यूटर सेन्टर का संचालन :—

(1) संस्था में आवेदन प्रस्तुत करने पर उनको कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराया जायेगा.

(2) उर्दू व अरबी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु माह फरवरी व मार्च में आवेदन कर एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र का कोर्स केन्द्र से कराया जायेगा.

(3) उर्दू पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर में कम्प्यूटर कोर्स संचालित किये जायेंगे एवं चॉईस सेन्टर का पंजीयन संस्था द्वारा कराकर संचालन किया जायेगा.

(4) केन्द्र में उर्दू लिखने एवं पढ़ने सीखने हेतु आवेदन कर उर्दू सीखने हेतु उर्दू की कक्षाएँ संचालित किया जायेगा.

कम्प्यूटर सेन्टर का मन्टेनेंस अनुबन्धित संस्था द्वारा किया जायेगा.

पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर हेतु नियम एवं शर्तें 2022

पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर के संचालन हेतु नियम एवं शर्तें हिस्सा अव्वल में निम्नानुसार अतःस्थापित किया जाता है :-

01. पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर नियमावली 2017 (यथासंशोधित 2022) के अनुसार पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर संचालित होगा.
02. छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों व पत्रिकाओं का विक्रय केन्द्र पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर रहेगा. पुस्तकें-पत्रिकाएँ बिक्री से प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत संस्था को प्रदान किया जायेगा.
03. अनुबन्धित सेन्टर में उर्दू पढ़ने/लिखने सीखने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कम-से-कम पांच आवेदक होने पर कक्षा संचालित की जायेगी उर्दू कक्षा संचालित करने हेतु सामग्री छ.ग. उर्दू अकादमी द्वारा प्रदाय की जायेगी.
04. एनसीपीयुएल नई दिल्ली के द्वारा उर्दू एवं अरबी एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स छ.ग. उर्दू अकादमी में संचालित है. सेन्टर में उर्दू एवं अरबी एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रतिवर्ष माह फरवरी एवं मार्च में आवेदन जमा किया जाता है. आवेदक को कोर्स करवाया जायेगा.
05. पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर को सुदृढ़ करने हेतु जनभागीदारी के सहयोग से सदस्य बनाकर किया जायेगा. इसके लिये 100/-रु. सदस्यता शुल्क निर्धारित किया गया है.
06. पुस्तकालय जिस क्षेत्र में संचालित है वहां के समाजसेवी पुस्तकालय के लिये 5000/- रु. या समतुल्य सामग्री प्रदान करने पर उसे संस्था का अजीवन सदस्य माना जायेगा एवं सलाहकार संचालन समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा.
07. पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर संचालन समिति द्वारा बैंक में खाता संधारित किया जायेगा.
08. छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा अधिकृत व्यक्ति/निरीक्षण दल द्वारा पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर का आकस्मिक निरीक्षण/जाँच की जा सकेगी.
09. **चॉईस सेन्टर स्थापना एवं संचालन** — छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चॉईस सेन्टर हेतु ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से चॉईस सेन्टर संचालन का पंजीयन किया जाता है. जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :-
 01. ऑनलाईन पंजीयन हेतु आवेदक का आधार-कार्ड, पेन कार्ड, एक केन्सल चेक एवं दुकान या उपलब्ध जगह का फोटो एवं पन्द्रह सौ रुपये ऑनलाईन आवेदन के साथ ऑनलाईन भुगतान करना है.
 02. ऑनलाईन टी.सी.ए. परिक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है.
 03. एक माह के पश्चात् पंजीकृत चॉईस सेन्टर का पंजीयन क्रमांक (आई.डी.नम्बर) जारी होगी.

04. उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् संस्था को जिलाध्यक्ष कार्यालय से अनुबंध के लिये स्वयं के नाम से पांच हजार रुपये की एफ.डी. अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा.
05. choise.gov.in, csc, chips के अन्तर्गत आने वाली शासन की सभी सेवायें इसमें उपलब्ध होंगी एवं शासन द्वारा दिया जाने वाले आय प्रमाण, मूलनिवास प्रमाण, जन्म प्रमाण-पत्र आदि सभी सेवाये हेतु शासन से अधिकृत होगा.
06. चॉईस सेंटर आनलाईन पंजीयन की प्रक्रिया संस्था द्वारा स्वयं की जायेगी.
10. सेन्टर में कम्प्यूटर उपलब्ध होने से ऑनलाईन लाईब्रेरी की सुविधा प्रारंभ की जायेगी.
11. अनुबंधित सेन्टर में कार्यरत पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर सहायक को समय-समय पर प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के द्वारा कराया जायेगा.
12. राज्य के समस्त अनुबंधित सेन्टर को मुख्यालय छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी से ऑनलाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जायेगा.
13. छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा समय-समय पर जारी नियम-निर्देशों का सेन्टर द्वारा पालन किया जायेगा एवं सेन्टर में कम्प्यूटर का संचालन संस्था के सुविधानुसार संचालित किया जाये संचालन की समय की जानकारी अकादमी को उपलब्ध कराया जाये.
14. उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू पुस्तकालय, वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर स्थापना के पश्चात् केन्द्र संचालन हेतु अनुबंधित संस्थानों को उर्दू-हिन्दी-अंग्रेजी पुस्तक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, कम्प्यूटर सेट, फर्नीचर, सेन्टर संचालन हेतु डी.एम.एफ. (DMF) मद से अनुदान हेतु जिलाध्यक्ष को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा.
15. नियमावली 2017 (यथासंशोधित 2022) के अनुसार सेन्टर संचालन में उर्दू पुस्तकालय व वाचनालय एवं कम्प्यूटर सेन्टर को सम्मिलित किया गया है, यदि किसी केन्द्र में उर्दू पुस्तकालय व वाचनालय या कम्प्यूटर सेन्टर हेतु अनुबंधित संस्था द्वारा आवेदन-पत्र पर विचार कर पृथक-पृथक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी.
16. छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा सलाहकार संचालन समिति का गठन किया जायेगा. अनुबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक छः-छः माह में बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण जिलाध्यक्ष एवं अकादमी को उपलब्ध कराना अनिवार्य है.
17. छ.ग. उर्दू अकादमी द्वारा फर्नीचर (आलमारी, कुर्सी, टेबल आदि) उर्दू साहित्य की तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, समाचार-पत्र/पत्रिकाएँ/लाईब्रेरी सदस्यता, स्टॉक, समाचार पत्र/पत्रिकाएँ वितरण, सुझाव रजिस्टर, चश्म-ए-उर्दू त्रैमासिक पत्रिकाएं छ.ग. उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, हिन्दी से उर्दू सीखने/पढ़ने की अभ्यास पुस्तकें संस्था को पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर हेतु निशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी. (मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पत्रिका, समाचार-पत्र अध्ययन केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन के पश्चात् उपलब्ध कराया जायेगा)
18. पत्रिकाएं (मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक) समाचार-पत्र केन्द्र में प्रकाशक के द्वारा सीधे बुकपोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा. उसका सत्यापन कर छ.ग. उर्दू अकादमी को प्रेषित किया जायेगा. जिसके अनुसार प्रकाशक को पत्रिकाएं, समाचार पत्र का भुगतान अकादमी द्वारा किया जायेगा.
19. पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र एवं कम्प्यूटर सेन्टर द्वारा प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल से मार्च तक के किये गये कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन माह अप्रैल में निर्धारित प्रारूप में छ.ग. उर्दू अकादमी को भेजना अनिवार्य होगा.
20. सेन्टर में गैरकानूनी, अनैतिक क्रिया कलाप वर्जित है. राजनैतिक एवं व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा, यदि ऐसा पाया जाता है, तो संस्था पर कठोर कार्यवाही किया जायेगा.

सरोजनी टोप्पो,
अवर सचिव.

**कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील डभरा,
जिला-सक्ती (छ.ग.)**

सक्ती, दिनांक 10 जनवरी 2023

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 81.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक-3413 दिनांक 23-09-2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14-10-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	हीरापुर	73/1	0.112
			73/2	0.083
			75	0.070
			76/1	0.018
			74	0.258
			80/2	0.028
			81/1	0.092
			82/2	0.111
			82/1	0.290
			83/2	0.162
			133/2	0.059
			133/3	0.145
			212/2	0.028

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			212/1	0.153
			210/1	0.216
			186/1	0.02
			134/2	0.013
			144/2	0.146
			144/3	0.049
			145/2	0.129
			145/1	0.004
			140	0.036
			185	0.135
			146/3	0.182
			146/2	0.050
		188, 190, 192, 269		0.270
		189		0.008
		166/6		0.053
		146/1		0.091
		187/2		0.156
		181/2		0.012
कुल योग			34	3.179

सक्ती, दिनांक 10 जनवरी 2023

“प्रारूप-घ”

(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 82.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक-3401 दिनांक 23-09-2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14-10-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	मौहापाली	450/1	0.176
			450/2, 451	0.206
			441/1	0.053
			441/6	0.063
			427/5	0.004
			441/4	0.042
			441/7	0.031
			441/9	0.013
			441/3	0.036
			441/2	0.031
			429/3	0.004
			427/3	0.059
			441/5	0.039
			440/2	0.082
			440/3	0.012
			440/1	0.012
			439/5	0.051
			439/4	0.03
			439/3	0.084
			439/1	0.153
			423/1	0.138
			430/7	0.098
			430/8	0.024
			299/2	0.025
			299/3	0.027
			428/3	0.066
			302/2, 426/2	0.040
			425	0.042
			423/2	0.139
			421	0.002
			304/4	0.113
			304/5 ग	0.087
			304/8 क	0.105
			304/9 ग	0.081
			304/9 ख	0.024
			304/10 ख	0.065
			304/10 क	0.045
			306/5	0.032
			307/2	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			306/3	0.036
			306/1	0.021
			306/4	0.02
			306/2	0.028
			280	0.025
			279/6	0.162
			279/5	0.004
			268/7	0.042
			268/9	0.172
			268/25	0.061
			268/34	0.028
			268/3	0.156
			268/37	0.037
			271/1 घ	0.03
			271/1 ख	0.062
			271/3	0.152
			268/57	0.004
			422	0.002
			259/1 प/च	0.004
		271/1 क, 271/ च, 271/1 छ		0.061
			270/1	0.068
			270/2	0.034
			259/2घ	0.012
			268/10	0.083
			268/28	0.061
			268/19	0.066
			268/8	0.066
			259/2 ख	0.005
			84/1	0.093
			84/2	0.086
			84/5	0.042
			85/2	0.070
			80/2	0.156
			85/3	0.004
			64	0.115
			85/1	0.036
			63/1	0.056
			63/2	0.053
			60/2	0.004
			61/2	0.007
			12/23	0.105
			12/24	0.105
			59/4	0.116
			14/2	0.136
			15/2	0.096
			16	0.143

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14/3	0.157
			14/1	0.082
			62	0.071
			60/1	0.040
		कुलयोग	93	5.632

सक्ती, दिनांक 10 जनवरी 2023

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 83.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक-3409 दिनांक 23-09-2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14-10-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	बरहागुड़ा	228/1	0.142
			227/1	0.093
			230/3	0.032
			227/2	0.126
			228/2	0.143

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			229/2	0.207
			231	0.036
		कुल योग	7	0.779

सक्ती, दिनांक 10 जनवरी 2023

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

क्रमांक 84.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा को अधिसूचना क्रमांक-3007 दिनांक 23-09-2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी लारा परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14-10-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सक्ती	डभरा	कोसमंदा	123/3, 130	0.074
			123/1	0.086
			123/2	0.170
			124	0.048
			101/23 क	0.136
			101/22 क	0.034

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			101/19 क	0.124
			101/18 क	0.019
			101/17 क	0.006
			101/20 क	0.054
			125/3, 126/3	0.008
		कुल योग	13	0.759

दिव्या अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय छ.ग. राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार, रायपुर
स्टेट गेस्ट हाउस “पहुना” के पीछे, केनाल रोड, शांति नगर, रायपुर, छ.ग.

रायपुर दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्रमांक/छगरापुजप्रारा/शिका./91-A/22.—छ.ग. शासन गृह पुलिस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-62/2008/गृह-दो रायपुर दिनांक 19-12-2022 के परिपालन में छ.ग. राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार रायपुर में सदस्य के पद पर पुनः नियुक्ति पर श्रीमती रामकली यादव के द्वारा आज दिनांक 20-12-2022 के (पूर्वान्ह) में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया है.

हस्ता./-
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th December 2022

No. 1253/Confdl./2022/II-2-1/2022.—The following Member of Higher Judicial Service, as mentioned in Column No. (2) of the table below, who has been reinstated in service vide Order No. 12413/3286/21-B(I)/C.G./2022 dated 16-11-2022 issued by the State Government in compliance with the order dated 29-07-2022 passed by the Division Bench of this High Court in Writ-Appeal No. 281/2022 (High Court of Chhattisgarh Vs. Ganesh Ram Berman & Others) and order dated 13-05-2022 passed by the Single Bench of this High Court in Writ Petition (S.) no. 825/2017 (Ganesh Ram Berman Vs. High Court of Chhattisgarh & Others), is posted at the place and in the capacity as shown against his name in Column No. (4) of the table below, with a direction to assume charge of his office by 05-01-2023.

The following Member of Higher Judicial Service, is also appointed as Additional Sessions Judge for the

Sessions Division mentioned in Colum No. (3) of the table below, from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No.	Name	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Ganesh Ram Burman, Ward No. 19, Near Pre matric Girls Hostel, Indira Nagar, Janjgir, District-Janjgir-Champa (C.G.).	Jashpur	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Jashpur.

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.
